

March  
2022

# समाचार पत्रों से चयित अंश Newspapers Clippings

A Daily service to keep DRDO Fraternity abreast with DRDO Technologies, Defence Technologies, Defence Policies, International Relations and Science & Technology

खंड : 47 अंक : 57 24 मार्च 2022

Vol. : 47 Issue : 57 24 March 2022



रक्षा विज्ञान पुस्तकालय  
Defence Science Library  
रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केंद्र  
Defence Scientific Information & Documentation Centre  
मेटकॉफ हाउस, दिल्ली - 110 054  
Metcalf House, Delhi - 110 054

# CONTENTS

S. No.	TITLE		Page No.
<b>DRDO News</b>			<b>1-2</b>
<b>DRDO Technology News</b>			<b>1-2</b>
1.	ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का DRDO ने किया सफल परीक्षण, भारत ने दुनिया को दिखाई ताकत	<i>Aaj Tak</i>	1
2.	India successfully test fires surface-to-surface BrahMos supersonic cruise missile	<i>abp</i>	2
<b>Defence News</b>			<b>3-7</b>
<b>Defence Strategic: National/International</b>			<b>3-7</b>
3.	नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (एनटीएसी) की बैठक आयोजित की गई	<i>Press Information Bureau</i>	3
4.	Naval technology acceleration council (NTAC) meeting	<i>Press Information Bureau</i>	4
5.	भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवाजी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया	<i>Press Information Bureau</i>	5
6.	Indian Navy's COE (ME) at INS Shivaji recognised as centre of excellence in marine engineering by ministry of skill development and entrepreneurship (MSDE)	<i>Press Information Bureau</i>	6
7.	MOD stresses self-reliance in Defence procurement	<i>Indian Defence News</i>	6
<b>Science &amp; Technology News</b>			<b>7-10</b>
8.	Ecosystem towards innovation	<i>Press Information Bureau</i>	7
9.	Newspace India to open price bids for industries making PSLV rocket next month	<i>Indian Defence News</i>	9



Wed, 23 Mar 2022

### **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का DRDO ने किया सफल परीक्षण, भारत ने दुनिया को दिखाई ताकत**

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल परीक्षण को देखने के लिए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारी मौजूद थे। रक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। वह परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अंडमान और निकोबार के द्वीप क्षेत्र में हैं। इससे पहले 8 दिसंबर 2021 वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमके-1 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल ने तय मानकों को पूरा करते हुए दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सुखोई-30 एमके-1 (Sukhoi-30 MK-1) फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है।

उधर, भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड एयर लॉन्च वर्जन तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। यानी हमारे लड़ाकू विमान हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही तबाह कर सकते हैं। भारत अब लगातार टैकिट कल मिसाइलों की रेंज को बढ़ा रहा है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से ही मिसाइल की रेंज में 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई-30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात की गई हैं। यह मिसाइलें बेहद सटीक और शक्तिशाली हैं और दुश्मन के कैंप को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं।

<https://www.aajtak.in/india/news/story/drdo-successfully-testfired-the-surface-to-surface-brahmos-supersonic-cruise-missile-in-the-andaman-and-nicobar-islands-ntc-1433594-2022-03-23>



*Wed, 23 Mar 2022*

## **India successfully test fires surface-to-surface BrahMos supersonic cruise missile**

BrahMos Supersonic Cruise Missile: Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari congratulated on the successful test-firing of missile. The Defense Research and Development Organisation (DRDO) on Wednesday "successfully" test-fired surface to surface BrahMos supersonic cruise missile which is an extended range missile that can hit its target with pinpoint accuracy, as reported by news agency ANI.

Air Chief Marshal Vivek Ram Chowdhury and other defense officials witnessed the missile test. The defense official informed that the missile hit its target accurately. Meanwhile, Air Chief Marshal VR Chaudhari congratulated on the successful test-firing of missile "Air Chief Marshal VR Chaudhari congratulated on the successful test-firing of surface to surface BrahMos supersonic cruise missile. He is in the Island territory of Andaman & Nicobar to review operational preparedness," said Defence officials as quoted by ANI.

Earlier, news agency ANI had quoted sources saying that the range of BrahMos supersonic cruise missiles had recently been extended to 500 km. This is made possible by simply upgrading the software. No changes have been made to the missile. Now the missile has a range of 800 km. It can also be dropped from high altitudes by fighter jets. The Indian Air Force has deployed BrahMos cruise missiles on its 40 Sukhoi aircraft. These missiles can be more deadly and can hit the enemy from a greater distance.

The BrahMos missile has been developed in collaboration with Russia. These missiles fly at three times the speed of sound i.e. 2.8 Mach (Mach number is the ratio of an object's speed in a given medium to the speed of sound in that medium). It can also dodge the radar. Earlier its range was 290 km, which was increased to 350-400.

The air version of the BrahMos supersonic cruise missile was successfully tested with the Sukhoi 30 MKI on December 8 last year. Now there are plans to deploy them on other fighter jets as well.

<https://news.abplive.com/news/india-successfully-testfired-surface-to-surface-brahmos-supersonic-cruise-missile-in-andaman-nicobar-1521318>



पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

Wed, 23 Mar 2022 6:19PM

## नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (एनटीएसी) की बैठक आयोजित की गई

नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (एनटीएसी) ने 23 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में अपनी दूसरी बैठक की। यह नौसेना नवोन्मेषण और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ) की शीर्ष निकाय है। इस बैठक की अध्यक्षता नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस एन घोरमडे ने की। इसमें परिषद ने चालू और प्रस्तावित स्वदेशीकरण व नवाचार मामलों की समीक्षा की।

13 अगस्त, 2020 को माननीय रक्षा मंत्री ने एनआईआईओ की स्थापना की थी। इसके बाद हर महीने औसतन दो से अधिक आईपीआर आवेदन नौसेना कर्मियों ने दायर किए हैं। सैन्य विशिष्टता के साथ-साथ दोहरे उपयोग वाले नवाचारों के लिए पेटेंट आवेदन दायर किए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम (एनआरडीसी) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कई दोहरे उपयोग वाले उत्पादों को पहले ही एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

भारतीय नौसेना पूरी तरह सक्रिय और डायनेमिक (गतिशील) स्वदेशीकरण निदेशालय के साथ स्वदेशीकरण में सबसे आगे रही है। इसके अलावा नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एनआईआईओ के तहत एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ (टीडीएसी) भी गठित किया गया है।

स्वदेशीकरण की दिशा में प्रमुख पहलों में उद्योग आउटरीच कार्यक्रम (अहमदाबाद, भुवनेश्वर और कोयंबटूर में आयोजित) और स्वदेशीकरण व आत्मनिर्भरता (सीआईएसआर) के लिए एक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल हैं।

टीडीएसी, घरेलू नौसैनिक नवाचारों को आगे बढ़ाने के अलावा अकादमिक और उद्योग के साथ भी जुड़ा हुआ है। वहीं, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम) के समन्वय में उद्योग जगत के साथ एक ऑनलाइन मासिक वार्ता भी शुरू की गई है। इसके अलावा डीप टेक स्टार्टअप्स को

'नवाचार उद्योग साझेदार' के रूप में भी मान्यता दी जा रही है और उन्हें नौसेना की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हैंडहोल्डिंग प्रदान की जाती है।

'इंडियन नेवल स्टूडेंट्स टेक्निकल एंगेजमेंट प्रोग्राम' (इन स्टेप) प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के युवा मस्तिष्कों को इससे जोड़ने को लेकर नेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर काम करने के लिए पांच महीने की ऑनलाइन इंटरनशिप प्रदान करता है। एनटीएसी की बैठक के दौरान इन स्टेप के तहत एक 'ओपन चैलेंज' की घोषणा की गई। इसे एसआईडीएम और BharatShakti.in के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसके लिए तीनों संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

<https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1808893>



**Press Information Bureau**  
**Government of India**

**Ministry of Defence**

*Wed, 23 Mar 2022 6:19 PM*

## **Naval technology acceleration council (NTAC) meeting**

Naval Technology Acceleration Council (NTAC) the apex body of the Naval Innovation and Indigenisation Organisation (NIIO) held its 2<sup>nd</sup> meeting at New Delhi on 23 March 2022. Chaired by VAdm SN Ghormade, Vice Chief of Naval Staff, the NTAC reviewed the ongoing and proposed indigenisation and innovation cases.

On an average more than two IPR applications have been filed by naval personnel every month since the launch of the NIIO by the Hon'ble RakshaMantri on 13 August 2020. Patent applications have been filed for military specific as well as dual-use innovations. Many dual use products have also already been transferred to the MSMEs for mass production through the National Research & Development Corporation (NRDC) and the Rashtriya Raksha University

Indian Navy has been at the forefront of *indigenisation* with a fully functional and dynamic Directorate of Indigenisation. Additionally, a technology Development Acceleration Cell (TDAC) has been created under NIIO to focus on *innovation*. Major initiatives towards Indigenisation include industry outreach programmes (conducted at Ahmedabad, Bhubaneswar and Coimbatore) and the proposal set up a center for Indigenisation and Self-Reliance (CISR).

TDAC also engages with the academia and the industry in addition to channeling in-house naval innovations. An online monthly interaction with the industry in coordination with the Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) has also been instituted. Deep tech startups are also being recognised as 'Innovation Industry Partners' and are provided handholding to better understand naval requirements. To engage young minds in premier educational institutions the 'Indian Naval Students Technical Engagement Programme' (IN STEP) provides a five month online internship to work on naval problem statements. An 'open challenge' under IN STEP was announced during the NTAC meeting and will be undertaken in partnership with *SIDM* and *BharatShakti.in*. An MoU was signed between the three organisations to this effect.

<https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1808821>



पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

Wed, 23 Mar 2022 3:17 PM

## भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवाजी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग (एमई) के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र 22 मार्च 2022 को नई दिल्ली में मंत्रालय के मुख्यालय, श्रम शक्ति भवन में आईएनएस शिवाजी के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर अरविंद रावल को एमएसडीई के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस द्वारा सौंपा गया। एमएसडीई द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता किसी भी सैन्य संगठन के लिए अपनी तरह की पहली और कौशल तथा प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में स्थापना के निरंतर प्रयासों का अगला कदम है।

आईएनएस शिवाजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (समुद्री इंजीनियरिंग) की स्थापना वर्ष 2014 में एक व्यापक शासनादेश के साथ की गई थी, जिसके प्रमुख उद्देश्यों में नौसेना अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल करना, अनुसंधान एवं विकास और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण करना तथा क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों के इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करना शामिल हैं। आईएनएस शिवाजी में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के गहन मूल्यांकन तथा भारतीय नौसेना, मित्र देशों की नौसेनाओं और पूरे इकोसिस्टम में कर्मियों के कौशल को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के बाद इस उत्कृष्टता केंद्र को मान्यता दी गई थी।

यह मान्यता समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मित्र देशों की नौसेनाओं के लिए एक पसंदीदा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के रूप में आईएनएस शिवाजी की स्थिति को और बेहतर करेगी तथा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं विकास के लिए देश के भीतर व बाहर के प्रतिष्ठित उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।

<https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1808836>



Press Information Bureau  
Government of India

Ministry of Defence

Wed, 23 Mar 2022 3:17 PM

## **Indian Navy's COE (ME) at INS Shivaji recognised as centre of excellence in marine engineering by ministry of skill development and entrepreneurship (MSDE)**

The Centre of Excellence (Marine Engineering), INS Shivaji has been recognised as a Centre of Excellence in the field of Marine Engineering by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). The recognition certificate was handed over by the Secretary MSDE, Shri Rajesh Aggarwal, IAS to Commodore Arvind Rawal, Commanding Officer, INS Shivaji at the Ministry Headquarters, Shram Shakti Bhavan, New Delhi on 22 Mar 22.

Recognition as Centre of Excellence by MSDE is first of its kind for any military organisation and an indication of establishment's sustained efforts towards skill and technology development.

The Centre of Excellence (Marine Engineering), INS Shivaji was set up in 2014 with a broad mandate including induction of niche technologies for naval applications, undertaking quality research in collaboration with R&D and academic institutes of repute and providing engineering solutions for field level issues. The Centre was accorded the recognition after a thorough evaluation of the infrastructure & facilities available at INS Shivaji and the training being imparted towards enhancing the skills of personnel of Indian Navy, Friendly Foreign Navies and the entire ecosystem.

The recognition would further cement INS Shivaji's standing as a preferred training establishment for Friendly Foreign Navies in the field of Marine Engineering and enable the establishment to augment partnership with industry and academic institutions of repute within and outside the country for quality R&D.

<https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1808655>



Thu, 24 Mar 2022

## **MOD stresses self-reliance in Defence procurement**

Just a week after a Sweden-based think tank reported India was the largest global importer of weapons during 2017-21, the Ministry of Defence on Tuesday decided that requirements of modernising the armed forces would be sourced indigenously and imports would be allowed only as an exception. The decision was taken at a meeting of the Defence Acquisition Council (DAC).



## Approval to another satellite for forces

- To allow imports only as exception
- Nod to Rs8,357-cr capital acquisition proposals
- Another satellite (GSAT 7B) okayed for forces
- Rs380.43-cr procurements from start-ups, MSMEs

The DAC, chaired by Defence Minister Rajnath Singh, is the apex decision-making body of the MoD. Though the existing policy mandates an explicit okay from the DAC and the Cabinet Committee on Security for imports, the decision today made self-reliance as the key policy direction. The DAC accorded the “acceptance of necessity” for a new satellite for the forces called GSAT 7B. This is among the capital acquisition proposals worth Rs 8,357 crore cleared by the DAC.

Last November, the DAC approved a proposal of the Indian Air Force to get the GSAT-7C satellite with ground hubs for real-time connectivity. All proposals cleared today are under “Buy (Indian IDDM)” category with focus on indigenous design and development and manufacturing in India. Besides the satellite, the DAC okayed night sights, light vehicles and an air defence fire control radar. It also approved procurements worth Rs 380.43 crore to be sourced from start-ups and MSMEs.

On March 14, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) released a report saying India was the largest importer, accounting for 11 per cent of weapon imports during 2017-2021

<http://www.indiandefensenews.in/2022/03/mod-stresses-self-reliance-in-defence.html>

## Science & Technology News



**Press Information Bureau**  
**Government of India**

**Ministry of Science & Technology**

*Wed, 23 Mar 2022 6:42 PM*

## Ecosystem towards innovation

Creating an ecosystem to foster innovation in science & technology has been a part of Government’s Science and Technology (S&T) policy. The Science, Technology and Innovation (STI) Policy of 2013 encourages students/youth of the country towards the field of science & technology and innovation. The key elements of STI Policy include promoting the spread of scientific temper amongst all sections of society, enhancing skill for application of science among the youth from all social strata, making careers in science, research and innovation attractive enough for talented and bright minds.

Government has been implementing several schemes to encourage students/ youth of the country towards the field of science and technology. The “Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE)” is a major scheme to attract, motivate, nurture and train

talented and meritorious students to study science subjects, inculcate scientific temperament and opt for careers in Research and Development (R&D) to build a pipeline of quality manpower, thereby widening the R&D manpower base of the country. Close to 52,000 young students of class 6th - 10th receive the INSPIRE Award MANAK (Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge) per year from recognized schools across the country. About 20,000 students per year attend INSPIRE Internship Camps to experience the joys of creative pursuit of science.

The vision of Atal Tinkering Lab initiative is to 'Cultivate 1 Million children in India as Neoteric Innovators'. The objective of this scheme is to foster curiosity, creativity and imagination in young minds and inculcate skills such as design mind-set, computational thinking, adaptive learning, physical computing, rapid calculations, measurements etc. These ATLS are equipped with latest emerging technologies such as electronics, IoT, 3D printing, Robotics, etc. Around 9600 ATLS have been setup in various schools of the country.

Government has taken several steps to promote affordable and sustainable innovations in the field of science and technology. DST has launched National Initiative for Developing and Harnessing Innovations' (NIDHI) programme to strengthen the innovation value chain through Technology Business Incubators (TBIs). NIDHI provides much-needed support to innovators and entrepreneurs at different stages of their journey to take their innovative ideas to market and further scale up its operations. NIDHI-PRAYAS Shala specially assists innovators in their "idea to prototype journey" through grant funding of up to Rs. 10 lakh. Forty three PRAYAS Centres have been setup in various academic institutions to support innovators and entrepreneurs to test their ideas and make prototypes which is further developed as products and a startup.

The DST-NIDHI program aims to provide state-of-the art infrastructure for nurturing startups along with mentoring and funding support during pre-incubation, incubation and post incubation periods through startups incubators. These incubators support startups in various technology domains like agritech, manufacturing, electronics, IoT, health-tech, biotech, AI/ML, deep-tech etc.

For promoting affordable sustainable innovation in the field of science and technology, the National Innovation Foundation (NIF), an autonomous institution under DST organizes a biennial National Grassroots Innovation and Outstanding Traditional Knowledge Awards and for it, common people (including youth) share their ideas and innovations. NIF provides value-addition and incubation support to the innovators so that their technologies can reach the market. NIF has also set up NIF Incubation and Entrepreneurship Council (NIFentreC), a Technology Business Incubator, for setting up and incubating commercial ventures based on innovative technologies of common people of the country.

This information was given by Minister of State (I/C) of the Ministry of Science and Technology & Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh in a written reply in Lok Sabha today.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1808834>

*Thu, 24 Mar 2022*

## **NewSpace India to open price bids for industries making PSLV rocket next month**

NewSpace India Ltd - the commercial arm of Department of Space - will open the price bids submitted by three parties to make rocket Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) next month, as the next fiscal begins, said a senior official. NewSpace India Ltd - the commercial arm of Department of Space - will open the price bids submitted by three parties to make rocket Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) next month, as the next fiscal begins, said a senior official.

"The techno-commercial evaluation is on the verge of conclusion. Once that is done, the price bids submitted by the three industry consortiums will be opened," an NSIL official, not wanting to be identified, told IANS. The NSIL has the mandate of building, and launching rockets and satellites through industry partners and also providing space-based services through remote sensing and communication satellites. Last year, the company issued the Request for Proposal (RFP) from industries for making five PSLV rockets of the Indian Space Research Organization. Three proposals were from Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) and Larsen and Toubro Ltd, Bharat Electronics Ltd, Alpha Design and BEML Ltd, and Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL), it is learnt.

"Various committees went through the proposals that were received," the official said. Contacted by IANS, ISRO Chairman and Space Secretary S. Somanath, queried about the RFPs, said a decision has to be taken on the modalities. He also said the plan was to source five PSLV rockets from the selected industry but whether the industry players will be enthused to make investments to make that number is the question. According to the NSIL official, the selected consortium will be enabled to use the existing ISRO facilities. Asked about the investment that would be made by the parties who have submitted their proposals, the official said that would be told later.

The NSIL official said the selected industry player can use ISRO facilities for a fee, and it is the industry's responsibility to deliver the rocket. Queried about the ISRO role, the official said, the Indian space agency will also have a role in making the rocket in connection with some critical systems. After PSLV, the NSIL will issue an Expression of Interest (EOI) for making the ISRO's small rocket - Small Satellite Launch Vehicle (SSLV)-- which is under development.

The selection process for SSLV will be simpler as NSIL has the experience in choosing the industry partner for making the PSLV rocket. Further the SSLV is of simpler technology - it is powered by solid fuel motors. Following that will be the EOI for making ISRO's heavier rocket Geosynchronous Satellite Launch Vehicle MK-III (GSLV MK-III), the official added.

Meanwhile NSIL has issued an 'Interest Explanatory Note' to transfer ISRO's technology for making the small satellite - India Mini Satellite-1 (IMS-1) Bus. ISRO's UR Rao Satellite Centre (URSC) has developed a small satellite platform which would enable low cost access to space by providing a dedicated platform for payloads for earth imaging, ocean and

atmospheric studies, microwave remote sensing and space science missions with a quick turnaround time.

The satellite will have a payload mass of 30 kg and a life space of two years. According to NSIL, the Department of Space has authorized for technology transfer of IMS-1 Satellite Platform to suitable entrepreneurs/industry in India.

<http://www.indiandefensenews.in/2022/03/newspace-india-to-open-price-bids-for.html>

